भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 887

जिसका उत्तर मंगलवार, दिनांक 13 अगस्त, 2013 को दिया जाना है

राष्ट्रीय इलैक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन

887. श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय इलैक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन (एनएमईएम) भारत में इलैक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण का संवर्धन करेगा;

(ख) क्या सरकार ने इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए समर्पित चार्जिंग स्टेशनों के माध्यम से विश्वसनीय विद्युत सुलभता प्रदान करने का खाका तैयार किया है;

(ग) क्या पर्यावरण संरक्षण और कार्बन-डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के संदर्भ में इलैक्ट्रिक वाहनों के वास्तविक लाभ तभी प्राप्त होते हैं जब उन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से चार्ज किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार नवीकरणीय ऊर्जा वाले मिशन में चार्जिंग स्टेशनों की कतिपय प्रतिशतता को अनिवार्य उपबंध बनाने पर विचार कर रही है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रफुल पटेल)

(क): जी, हां।

(ख): जी, हां।

(ग): इलेक्ट्रिक वाहनों की सकल ऊर्जा खपत से उत्पन्न उत्सर्जनों में बहुत अधिक कमी आई है। पारंपरिक जीवाश्म ईंधन द्वारा सृजित विद्युत से चार्जिंग की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से चार्ज किए जाने के परिणामस्वरूप उत्सर्जनों में और अधिक कमी आएगी।

(घ)और(ड.) : यद्यपि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा वाले मिशन प्लान में चार्जिंग स्टेशनों की कतिपय प्रतिशतता को अनिवार्य उपबंध बनाने पर विचार नहीं कर रही है, फिर भी नवीकरणीय ऊर्जा की वहनीय उपलब्धता, प्रयोगात्मक व्यवहार्यता आदि पर निर्भर है कि मिशन में नवीकरणीय ऊर्जा के साथ लिंक की परिकल्पना की जा सके।

*****